कर्मकार इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, मद्रास

बनाम

पीठासीन अधिकारी एवं एक अन्य

11 जनवरी, 1990

[रंगनाथ मिश्रा, पी.बी. सावंत और के. रामास्वामी, न्यायमूर्तिगण]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 10(1)(डी)-कर्मकारों का गैर-नियोजन-का औचित्य-तथ्य के निष्कर्ष-साक्ष्य की मात्रा या उसका मूल्यांकन-क्या उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकता था।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226-तथ्य के निष्कर्ष-साक्ष्य की मात्रा या उसका मूल्यांकन-क्या हस्तक्षेप किया जा सकता था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत, राज्य सरकार ने औद्योगिक न्यायाधिकरण को यह प्रश्न निर्दिष्ट किया कि क्या अपीलकर्ता-कंपनी में कुछ कर्मकारों का गैर-नियोजन न्यायसंगत था, और यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार थे। नियोक्ता और कर्मकारों ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपने संबंधित विवरण दाखिल किए और कर्मकारों ने एक संशोधन चाहा जिसे न्यायाधिकरण ने अनुमत किया। नियोक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से संशोधन को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने यह विचार अपनाया कि पंचाट को ही चुनौती देते समय संशोधन पर आक्षेप किया जा सकता है।

पंचाट दिया गया और नियोक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल एक रिट याचिका में इसे आक्षेपित किया। उच्च न्यायालय ने अनुतोष को 131 अस्थायी कर्मचारियों तक सीमित रखा जिन्होंने 240 दिनों से अधिक कार्य किया है और 50 अन्य के संबंध में पंचाट को अपास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की थी। व्यथित होकर, नियोक्ता और कर्मकारों दोनों ने खंड पीठ के समक्ष अपीलें दाखिल कीं। खंड पीठ ने पाया कि जब तक संशोधन नहीं किया गया था, तब तक कर्मकारों का एक अलग दावा था जो अंततः

न्यायाधिकरण के समक्ष दबाया गया था, कि उन कर्मकारों की संख्या में बहुत भिन्नता थी जिनके लिए अनुतोष का दावा किया गया था, और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि यह सिद्ध नहीं हुआ था कि नियोक्ता ने किसी भी अस्थायी श्रमिक की सेवाओं को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार, नियोक्ता की अपील अनुज्ञात की गई और कर्मकारों की खारिज कर दी गई। व्यथित होकर, कर्मकारों ने विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें दाखिल की हैं।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमत करते हुए, इस न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: 1. संघ द्वारा अपनाया गया यह रुख कि 13.10.1980 को कार्य प्रदान नहीं किया गया था, इस तथ्य के आलोक में गलत था कि 186 में से अस्थायी कर्मकारों की एक पर्याप्त संख्या ने वास्तव में 13 वें और आगामी दो दिनों में कार्य किया था। संघ ने स्थायीकरण के अपने दावे को कार्यबंदी के साथ मिला दिया था जिसके कारण छंटनी हुई। संघ ने स्पष्ट रूप से अपनी गलती का तब एहसास किया जब कंपनी ने अपना प्रति-विवरण दाखिल किया जिसमें एक निश्चित दावा किया गया कि कर्मकारों के एक बड़े हिस्से ने अक्टूबर, 1980 के 13 वें, 14 वें और 15 वें दिन कार्य किया था। न्यायाधिकरण ने कर्मकारों द्वारा किए गए कार्य के दिनों के आधार पर स्थायीकरण के प्रश्न का परीक्षण किया। इसने पाया कि 186 में से 131 व्यक्तियों ने 240 दिनों तक कार्य किया। दोहरेपन या मृत्यु के कारण 186 की संख्या घटकर 181 रह गई थी। न्यायाधिकरण के अनुसार, शेष 50 ने कार्य के 240 दिन पूरे नहीं किए थे और इसलिए, वे स्थायीकरण के हकदार नहीं थे।[18 सी-डी]

2. हालांकि यह एक तथ्य है कि कर्मकारों ने बड़े-बड़े दावे किए थे जिन्हें वे सिद्ध करने में विफल रहे थे, यह न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के लिए था कि वे अभिलेख पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करें और निर्णय लें कि दावे का कौन सा हिस्सा विश्वसनीय था। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि 131 कर्मकारों ने 240 दिनों से अधिक का कार्य किया था, कुछ साक्ष्यों के आधार पर पहुँचा गया था; यह हो सकता है कि बेहतर विवरण और स्पष्ट साक्ष्य न्यायाधिकरण के समक्ष रखे जाने चाहिए थे। न्यायाधिकरण ने सही रूप से इस

आधार पर अनुतोष दिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ का अनुपालन नहीं किया गया था।[18 ई-एच]

3. न्यायाधिकरण द्वारा पाए गए और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्ट किए गए 131 कर्मकारों के स्थायीकरण के दावे को पुनर्स्थापित किया जाएगा। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों में पिछले वेतन का अनुतोष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह दिनांक 14.2.1986 और 5.5.1988 के इस न्यायालय के दो अंतरिम आदेशों द्वारा कवर न किया गया हो। ऐसे भुगतान जो किए जा चुके हैं, उन्हें वसूल नहीं किया जाएगा।

4. तथ्य के निष्कर्षों को अभिलिखित करने के लिए साक्ष्य की मात्रा या उसका मूल्यांकन संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आएगा।[18 जी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1986 की दीवानी अपील संख्या 596-597(एनएल)

मद्रास उच्च न्यायालय के 1983 की रिट अपील संख्या 1235 और 1984 की रिट अपील संख्या 72 में दिनांक 19.12.1985 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए एम.के. राममूर्ति, के.एस. जानकीरमन और जितेन्द्र शर्मा।

उत्तरदाताओं के लिए टी.एस. गोपालन, पी.एन. रामलिंगम और ए.टी.एम. संपत।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति- ये कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ की प्रेरणा पर विशेष अनुमति द्वारा दो अपीलें हैं और चुनौती दो रिट अपीलों में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उलटने वाले निर्णय को है- एक नियोक्ता-कंपनी द्वारा और दूसरी उनके संघ के माध्यम से कर्मकारों द्वारा दाखिल की गई है।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 11.5.1981 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 10(1)(डी) के अंतर्गत निम्नलिखित विवादों का एक संदर्भ औद्योगिक न्यायाधिकरण को दिया:

"क्या निम्नलिखित श्रमिकों का गैर-नियोजन न्यायसंगत है; यदि नहीं, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं? धन के रूप में दिए गए अनुतोष की गणना करना, यदि इसकी गणना की जा सकती हो।"

संदर्भ के साथ 186 कर्मकारों की एक सूची संलग्न थी। संघ स्वयं 1 अक्टूबर, 1980 को अस्तित्व में आया था। इसने 14.10.1980 को कंपनी को लिखा था कि अस्थायी कर्मचारियों द्वारा कई वर्षों की सेवा प्रदान किए जाने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा था और स्थायी कर्मकारों पर लागू होने वाले लाभ और सुविधाओं से वंचित किया गया था।

न्यायाधिकरण के समक्ष नियोक्ता और कर्मकारों ने अपने संबंधित विवरण दाखिल किए। 25.11.1981 को, कर्मकारों की ओर से एक संशोधन चाहा गया जिसे न्यायाधिकरण ने अनुमत किया। कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल करके संशोधन को चुनौती दी परंतु उच्च न्यायालय का यह विचार था कि संशोधन के औचित्य पर आक्षेप किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो, जबकि नियत समय में पारित पंचाट को ही चुनौती दी जा रही हो। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि 181 अस्थायी कर्मचारियों को पूर्ण पिछले वेतन के साथ पुन: नियोजित किया जाना चाहिए और 50 अन्य अस्थायी कर्मचारियों को भी पुन: नियोजित किया जाना चाहिए परंतु पिछले वेतन के बिना। यह निर्देश इस आधार पर दिया गया था कि समाप्ति से पहले अधिनियम की धारा 25 एफ की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था जो कि छंटनी के समान था।

कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल करके पंचाट पर आक्षेप किया। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि पिछले वेतन के साथ पुनरुद्धार का अनुतोष 131 अस्थायी कर्मचारियों तक ही सीमित होना चाहिए था क्योंकि केवल उन्होंने ही 240 दिनों तक कार्य किया था और 50 अन्य के संबंध में पंचाट को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि उन्होंने 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष दो रिट अपीलें दाखिल की गईं- पंचाट के पुष्टि करने वाले हिस्से को

चुनौती देते हुए कंपनी द्वारा 1983 की रिट अपील संख्या 1235 और पचास कर्मकारों को अनुतोष से इनकार करते हुए कर्मकारों के संघ द्वारा 1984 की रिट अपील संख्या 72।

खंड पीठ ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया। इसने पाया कि जब तक संशोधन नहीं किया गया था तब तक कर्मकारों का एक अलग दावा था जो अंततः न्यायाधिकरण के समक्ष दबाया गया था। खंड पीठ ने आगे पाया कि उन कर्मकारों की संख्या में बहुत भिन्नता थी जिनके लिए अनुतोष का दावा किया गया था। इसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कंपनी का प्रति-विवरण 1 अगस्त, 1981 को दाखिल किया गया था, और उस तिथि तक, संघ और कंपनी के संबंधित रुख स्पष्ट रूप से अलग थे। तब तक संघ का मामला यह था कि 13.10.1980 को और उससे कर्मचारियों का गैर-नियोजन था क्योंकि उस तिथि को अस्थायी कर्मचारियों को कार्य देने से मना कर दिया गया था; कंपनी का मामला यह था कि 13.10.1980 को, संदर्भ से जुड़ी सूची में से 130 अस्थायी कर्मचारियों ने वास्तव में कार्य किया था और उनमें से अधिकांश ने अक्टूबर, 1980 के 14 वें और 15 वें दिन भी कार्य किया था। 25 नवंबर, 1981 को, मूल दावा विवरण के संशोधन को यह कहकर चाहा गया:

> "संदर्भ की शर्तों के अनुबंध में उल्लिखित और इस विवाद द्वारा कवर किए गए 186 कर्मकारों के गैर-नियोजन से संबंधित विवाद को उठाने की ओर ले जाने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के वर्णन के संबंध में कुछ लोप और लिपिकीय-सह-टंकण संबंधी गलतियाँ थीं।"

संशोधित विवरण में आगे कहा गया:

> "15 अक्टूबर, 1980 को, तिमाही प्रबंधन ने उन श्रमिकों से कहा जिन्होंने उस दिन कार्य किया था कि उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं और उन्हें 16 अक्टूबर, 1980 से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनमें से कई श्रमिकों को 16.10.1980 को

गेट पर प्रवेश करने से रोक दिया गया था। संघ ने इन सभी मामलों के संबंध में गैर-नियोजन के पहले के मामलों के साथ भी विवाद उठाने का निर्णय लिया था।"

खंड पीठ ने पाया कि इस प्रकार एक पूरी तरह से नया मामला पेश करने का प्रयास किया गया था जिसमें 13.10.1980 को और उससे गैर-नियोजन के मामले को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 1980 के महीनों में गैर-नियोजन, और 16.10.1980 को और उससे गैर-नियोजन के एक विशिष्ट मामले में बदल दिया गया था। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अपीलों में दिए गए तर्कों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद खंड पीठ ने स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

"यह पूरा मुकदमा हमें यह आभास देता है कि यद्यपि अस्थायी श्रमिकों के गैर-स्थायीकरण की एक वैध शिकायत हो सकती है जिन्होंने रोजगार की लंबी अवधि पूरी की है, संघ पूरी तरह से उस स्थिति के लिए उत्तरदायी प्रतीत होता है जिसमें विवादित अस्थायी श्रमिकों ने खुद को पाया है, 141 व्यक्तियों के गैर-नियोजन और समाप्ति का एक स्पष्ट रूप से झूठा मामला रखा गया था। यह केवल बाद के चरणों में था कि संघ ने पाया कि ऐसे मामले को सफलतापूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता है और वास्तव में यह संघ की जानकारी में झूठा था और दावा विवरण के केवल एक हिस्से में संशोधन करके 16.10.1980 को समाप्ति का मामला पेश करने का प्रयास किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, स्वयं दावा विवरण में ही एक असंगति आ गई। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायाधिकरण ने, एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण अपनाते हुए, केवल इस साक्ष्य को स्वीकार कर लिया कि 131 व्यक्तियों को समाप्त कर दिया गया था, जब साक्ष्य, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, न केवल प्रारंभिक विवरण के विपरीत है, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त और अनुपयुक्त है कि कंपनी की ओर से समाप्ति की गई थी। केवल एक अस्थायी श्रमिक से यह कहना कि कोई कार्य नहीं है, अस्थायी श्रमिकों की स्थिति के अनुरूप

है और कार्डों को हटाने की बाध्यकारी परिस्थितियां या एक सकारात्मक विवरण कि अस्थायी श्रमिकों को बिल्कुल भी कार्य नहीं दिया जाएगा, वर्तमान मामले में गायब है। हमारे विचार में, न्यायाधिकरण का पंचाट स्पष्ट रूप से विकृत है क्योंकि न्यायाधिकरण ने संघ द्वारा अपनाए गए रुख में असंगति पर विचार तक नहीं किया है और न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस मामले में यह विचार अपनाने के लिए विवश हैं कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि कंपनी ने किसी भी कर्मचारी के नियोजन को समाप्त कर दिया था जो अस्थायी श्रमिक थे, और न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्ट इसके विपरीत निष्कर्ष को अपास्त किया जाना चाहिए।"

तत्पश्चात खंड पीठ ने अपनी अपील में संघ के रुख की स्थिरता का परीक्षण किया और यह माना कि छंटनी का तर्क स्थापित नहीं हुआ था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा अपील अनुज्ञात की गई और कर्मकारों की अपील खारिज कर दी गई। इस तरह एक ही पंचाट में से दो अपीलें इस न्यायालय के समक्ष लाई गई हैं।

हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है। उनके संबंधित रुख के समर्थन में लिखित प्रस्तुतियाँ भी दाखिल किए गए हैं।

हम यह विचार अपनाने की ओर प्रवृत्त हैं कि खंड पीठ ने मामले से निपटने में बहुत सख्त दृष्टिकोण अपनाया है। यह सत्य है कि संघ द्वारा अपनाया गया यह रुख कि 13.10.1980 को कार्य प्रदान नहीं किया गया था, इस तथ्य के आलोक में गलत था कि 186 में से अस्थायी कर्मकारों की एक पर्याप्त संख्या ने वास्तव में 13 वें और आगामी दो दिनों में कार्य किया था। संघ ने स्थायीकरण के अपने दावे को कार्यबंदी के साथ मिला दिया था जिसके कारण छंटनी हुई। संघ ने स्पष्ट रूप से अपनी गलती का तब एहसास किया जब कंपनी ने अपना प्रति-विवरण दाखिल किया जिसमें एक निश्चित दावा किया गया कि कर्मकारों के एक बड़े हिस्से ने अक्टूबर, 1980 के 13 वें, 14 वें और 15 वें दिन कार्य किया था।

न्यायाधिकरण ने कर्मकारों द्वारा किए गए कार्य के दिनों के आधार पर स्थायीकरण के प्रश्न का परीक्षण किया। इसने पाया कि संदर्भ से जुड़ी 186 की सूची में से 131 व्यक्तियों ने वास्तव में 240 दिनों तक कार्य किया था। दोहरेपन या मृत्यु के कारण 186 की संख्या घटकर 181 रह गई थी। न्यायाधिकरण के अनुसार, शेष 50 ने कार्य के 240 दिन पूरे नहीं किए थे और इसलिए, वे स्थायीकरण के हकदार नहीं थे। हमारा यह विचार है कि अभिलेख पर प्रकट होने वाले तथ्यों और परिस्थितियों में खंड पीठ के लिए कर्मकारों के दावे को पूरी तरह से खारिज करना उचित नहीं था। हालांकि यह एक तथ्य है कि कर्मकारों ने बड़े-बड़े दावे किए थे जिन्हें वे सिद्ध करने में विफल रहे थे, यह न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के लिए था कि वे अभिलेख पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करें और निर्णय लें कि दावे का कौन सा हिस्सा स्थिर रहने योग्य था। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि 131 कर्मकारों ने 240 दिनों से अधिक का कार्य किया था, कुछ साक्ष्यों के आधार पर पहुँचा गया था; यह हो सकता है कि बेहतर विवरण और स्पष्ट साक्ष्य न्यायाधिकरण के समक्ष रखे जाने चाहिए थे। साक्ष्य की मात्रा या तथ्य के निष्कर्षों को अभिलिखित करने के लिए उसका मूल्यांकन संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आएगा। संदर्भ से जुड़ी सूची में से 131 कर्मकारों ने कार्य के 240 दिन पूरे कर लिए थे, इस तथ्य के निष्कर्ष को, इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विक्षुब्ध नहीं किया जाना चाहिए था।

न्यायाधिकरण ने इस आधार पर अनुतोष दिया था कि अधिनियम की धारा 25 एफ की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया था। जैसा कि खंड पीठ ने पाया, और हमें एक अलग विचार अपनाने का कोई औचित्य नहीं मिलता है, नियोजन की समाप्ति का मामला वास्तव में नहीं बनाया गया था। उस आधार पर पूर्ण पिछले वेतन के साथ पुनरुद्धार का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए था। इसलिए, हम कर्मकारों के लिए उपलब्ध अनुतोष को ढालने की ओर प्रवृत्त हैं।

न्यायाधिकरण द्वारा पाए गए और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्ट किए गए 131 कर्मकारों के स्थायीकरण के दावे को पुनर्स्थापित किया जाएगा। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों में पिछले वेतन का अनुतोष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह दिनांक 14.12.1986 और 5.5.1988 के इस न्यायालय के दो अंतरिम आदेशों के अंतर्गत न आता हो। ऐसे भुगतान जो किए जा चुके हैं, उन्हें वसूल नहीं किया जाएगा।

पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे शुरू से अंत तक अपनी-अपनी लागत स्वयं वहन करें।

जी.एन. अपीलें अनुमत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।